का प्रयोग नहीं करते हैं तथा 2 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां योजना को पहले ही लागू कर दिया गया है, पहले से ही इसके अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) सरकार देश में उन सभी औद्योगिक केन्द्रों में, जहां बीमा योग्य जनसंख्या अधिक है, क०रा०बी० योजना को लागू करने की इच्छुक है। वर्ष 1990-91 के लिए योजना के क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार, इस योजना को देश के 60 नए औद्योगिक केन्द्रों पर लागू किया जाना है जिसमें लगभग 1.13 लाख अतिरिक्त कर्मचारी (बीड़ी कर्मकार सहित) आते हैं।

मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछले क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता दर

581. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 5 प्रतिशत के लगभग है;

(ख) यदि हां, तो क्या "साक्षरता टैकनॉलोजी मिशन" या आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में महिला साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की जा रही है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आवंटित की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश के अन्य राज्यों में भी जहां इस प्रकार की स्थिति है, कोई पहल की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां, मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं से संबंधित साक्षरता दर 3.6% है।

(ख) मध्य प्रदेश के साक्षरता प्रौद्योगिकी मिशन मुख्यत: प्रौढ़ शिक्षा के लिए है जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूल तथा आश्रम स्कूल सहित प्राथमिक शिक्षा का नेटवर्क तैयार करने प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति/वृत्तिका और योग्यता छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संबंधित सामग्री की पूर्ति जैसे कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केवल लड़कियों के लिए पृथक होस्टल भी स्थापित किए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं में साक्षरता की ऊंची दर को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक आधार पर आदिवासी बोलियां में शिक्षण शुरू किया गया है।

(ग) आदिवासी महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, में महिलाओं द्वारा शिक्षा अवसरों की पहुंच में पाई गई असमानता को दूर करने हेतु विशेष बल की व्यवस्था है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा सहित देश भर में महिलाओं की शिक्षा पर बल देने के साथ शुरू की गई हाल ही की कुछ कार्यनीतियों को दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। (नीचे देखिए) आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के लिए 550 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

देश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यनीतियां

1. **महिला समस्या** : इस कार्यक्रम का आधार एक रचनातंत्र का निर्माण करना है जिसमें महिलाओं को अपनी स्वयं की शिक्षा की योजना बनाने, उसे मानीटर करने तथा ज्ञान के एक नए

पिंड के रूप में उभरकर आने का अवसर दिया जाता है। इसके उद्देश्यों के अन्तर्गत महिलाओं को ग्राम स्तर पर शिक्षा योजना की प्रक्रिया में शामिल किया जाना तथा शैक्षिक निदेश जैसे, लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, ग्राम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा शिक्षण सामग्री का उत्पादन प्रदान किया जाना शामिल हैं। यह परियोजना गुजरात, कर्नाटक तथा उत्त प्रदेश के 10 जिलों में प्रारम्भ की गई है।

2. **अनऔपचारिक शिक्षा :** शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में लड़कियों के लिए अनऔपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 90 प्रतिशत सहायता विमुक्त की गई।

3. **प्रौढ़ शिक्षा :** निम्नलिखित कार्यक्रमों सहित अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :-

-- प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में कम से कम 50% महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अधिक संख्या में प्रौढ़ महिला शिक्षार्थी का संचालन करना।

-- न्यूनतम अर्हताओं में छूट देकर, बड़ी संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं जैसे अनुदेशक, जन शिक्षक नियालम के प्रेरकों (जे.एन.एम.) की नियुक्ति करना।

--ऐसे अनुदेशकों की शिक्षा जारी रखने के लिए व्यवस्था करना।

--कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी।

--बड़ी संख्या में स्वैच्छिक एजेंसियों को, विशेषकर महिलाओं के लिए कार्यरत, शामिल करना ;

-- महिला कार्यकर्ताओं की ओर श्रमिक विद्यापीठ द्वारा अधिक ध्यान देना।

-- प्रभावकारी एजेंट के रूप में महिलाओं में समानता को प्रोत्साहित करने अधिकार देने के लिए विशेष अनुस्थापन तथा महिला अनुदेशकों को प्रशिक्षण देना।

--महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तयार करना जो नया कौशल प्रदान करने से समबद्ध हो उनके वर्तमान कौशल की उन्नति करना तथा नए आय संवर्धन क्रियाकलाप तैयार करना।

-- साक्षरता कौशल रखने के लिए अवसरों का सृजन और प्रावधान तथा इस ज्ञान को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उपयोग करना।

-- केन्द्र तथा राज्य समाज कल्याण बोर्डों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करना तथा

-- महिला साक्षरता तथा उनके अधिकारों पर फिल्म का निर्माण करना तथा दूरदर्शन के माध्यम से उनका प्रदर्शन करना।

Prices for groundnut oil in Rajkot and Ahmedabad

582. SHRI RAOOF VALIULLAH : Will the Minister **of** AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against National Dairy Development Board **for** purchasing edible groundnut oil from open market thereby pushing up its retail prices to an unprecedented level, if so, what action Government have taken in the matter;